C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol. XIX, Ninth Session, 2016/1938 (Saka)
No. 20, Friday, August 12, 2016/Shravana 21, 1938 (Saka)

SUBJECT	PAGES
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 381 to 387	7-53
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 388 to 400	54-80
Unstarred Question Nos. 4371 to 4600	81-477

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 479-500

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
Minutes 500

STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY
Statements 501-503

STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT
12th Report 504

STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS
198th Report 504

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 84th and 91st Reports of the Standing Committee on Health and Family Welfare on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Ministry of AYUSH (Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy)

Shri Shripad Yesso Naik 505

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 12th and 15th Reports of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers pertaining to the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers

Shri Mansukh L. Mandaviya 505-506

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 6th to 9th Reports of the Standing Committee on Defence pertaining to the Ministry of Defence

Dr. Subhash Ramrao Bhamre 507

RESOLUTION BY THE SPEAKER
Restoration of peace and normalcy
in Jammu and Kashmir 511-512

VALEDICTORY REFERENCE 513-516

NATIONAL SONG 516

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 517

Member-wise Index to Unstarred Questions 518-522

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 523

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 524

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, August 12, 2016/Shravana 21, 1938 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I cannot hear anything. What is this happening?

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : उदित राज जी, आज क्या बात है?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : भूरिया जी, बैठिए। आप सब बैठिए।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: After Question Hour, I will allow you.

… (*Interruptions*)

11.01 hours

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Now, Question Hour, Shri Bidyut Baran Mahato.

(Q. 381)

श्री विद्युत वरण महतो : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। आज विश्व में सबसे घातक रोग यदि कोई तेजी से बढ़ता जा रहा है तो वह हृदय रोग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2020 तक भारत में पूरे विश्व की तुलना में सर्वाधिक हृदय रोगी होंगे। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष लगभग एक करोड़ लोगों को दिल का दौरा पड़ता है, इसलिए इस संबंध में मेरा पहला प्रश्न है कि क्या सरकार जानती है कि बड़ी-बड़ी कंपनियां भारत में हृदय रोग की दवाइयां बेच रही हैं? एनजियोप्लास्टी के ऑपरेशन में डॉक्टर दिल की नली में एक स्प्रिंग डालते हैं, जिसे कोरोनरी स्टंट कहते हैं। क्या यह बात सही है कि यह स्टंट विदेशों में, अमेरिका में बनता है और इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ तीन डॉलर यानी 150 रुपये से लेकर 180 रुपये तक है? इस स्टंट को भारत में लाकर तीन से पांच लाख रुपये में बेचा जाता है। इसके मूल्य नियंत्रण की दिशा में सरकार द्वारा क्या उपाय उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते): माननीय अध्यक्ष जी, जैसे माननीय सदस्य ने कहा है कि यह प्रश्न मूलत: नली से संबंधित है और इसके लिए हमारे देश में, विशेषकर हमारा यह मंत्रालय कार्यरत है। उन्होंने कोरोनरी के बारे में एक समिति का गठन किया है, जो स्टंट की अनिवार्यता से संबंधित एक प्रोफेसर वाई.के.गुप्ता, विभागाध्यक्ष हैं और जो थर्मोकॉलोजी के प्रोफेसर हैं, उनको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। उनकी अध्यक्षता में इसकी जांच हुई है। इसके बाद इसके लिए रेट निर्धारण की जो प्रक्रिया है, इस कमेटी के माध्यम से उसको पूरा करने का यह एक प्रयास है। उसकी रिपोर्ट भी सबमिट हो गई है।

श्री विद्युत वरण महतो : माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा दूसरा प्रश्न है कि देश में कोरोनरी स्टंट का आयात मूल्य कितना है और इसे देश में रोगियों को कितने दाम पर बेचा जा रहा है? इस स्टंट की वार्षिक आवश्यकता कितनी है और कितनी पूर्ति होती है? क्या सरकार स्टंट की कीमत को एन.पी.पी.ए. के तहत नियंत्रित करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो इसके आने पर एन.पी.पी.ए. के तहत मूल्यों में कितनी कमी आएगी?

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, विभाग ने यह लिस्ट जारी की है और मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस प्रकार की व्यवस्था है। जहां तक औषध क्षालित स्टेंट्स का सवाल है, आप देखेंगे तो वर्ष 2011, वर्ष 2012 और वर्ष 2013 में रेटों का जो निर्धारण हुआ था, उसमें

इसकी कीमत 23,625 रुपये है। अगर आप पिछले इसके पिछले दामों को देखेंगे तो यह सबसे कम है। वर्ष 2011 में इसकी कीमत 65,000 रुपये थी, लेकिन आज यह 23,625 रुपये है। यह बहुत बड़ा अंतर है और मैं यह कह सकता हूं कि वर्ष 2016 में भी इसकी कीमत 23,625 रुपये आंकी गई है। हमारे पास यह रेट मौजूद है।

HON. SPEAKER: Shri Anandrao Adsul – not present.

Shri B. Vinod kumar

SHRI B. VINOD KUMAR: Madam, it is good that the Government had accepted the recommendation of the Sub-Committee and they have included stents in the National List of Essential Medicines. There are some other medical devices like pacemakers, ortho implants, CT and MRI scans which play a crucial role in diagnosis as well as prevention and cure of lifesaving threatening diseases. I would like to know from the hon. Minister whether the Government is arriving at a policy to devise a National List of Essential Medical Devices to enlist such lifesaving devices and to cap their prices. The National List of Essential Medicines caps the prices. Likewise, is the Government designing any such policy as National List of Essential Medical Devices?

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : अध्यक्ष महोदया, यह एक प्रक्रिया है। समय-समय पर हम देश के प्रभावित लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से इस प्रक्रिया को करते रहते हैं। जो सिफारिशें आती हैं, उन सिफारिशों को ध्यान में रख कर दवाइयों को उस सूची में डालने का काम सरकार करती रहती है।

DR. PRITAM GOPINATH MUNDE: Madam Speaker, thank you very much for allowing me to ask this very important question. सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि आज तक हम कम्यूनिकेबल डिज़ीजेज से लड़ते आ रहे हैं, ऐसी हालत में नॉन-कम्यूनिकेबल डिज़ीज, जिन्हें हम लोग लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं, ऐसे रोगों का एन.एल.ई.एम. में समावेश करना सरकार की तरफ से बेहद सराहनीय कदम है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि एन.एल.ई.एम. में कोरोनरी स्टेटंस की क्या कीमत निर्धारित की गई है? Madam, I would like to ask one more question. अगर हमें 'अमृत' स्टोर्स की स्टेटवाइज लिस्ट उपलब्ध हो जाए, जिससे यह पता चले कि ये स्टेट में कहां-कहां पर

उपलब्ध कराये जायेंगे तो अच्छा होगा। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स से इनको लिंक्ड अप किया जाये तो रोगियों को काफी सुविधा होगी, मैं आपके माध्यम से यह सुझाव भी देना चाहती हूं।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: मैडम, 'अमृत' सरकार की एक नई पहल है। Affordable Medicine and Reliable Implant Treatment, इसके तहत हम कार्डिएक की दवा, कैंसर की दवा और दूसरी दवाइयां देते हैं। अभी तक सेन्ट्रल इंस्टीट्यूशंस में इसकी नौ शॉप्स खुली हैं। आने वाले एक महीने में सभी सेन्ट्रल इंस्टीट्यूशंस में इसकी शॉप्स खुल जायेंगी। हमारी इच्छा 300 'अमृत' मेडिसिन की शॉप्स खोलने की है। उसके लिए हमने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेज और हॉस्पिटल्स में हमें जगह दें, उस जगह पर हम 'अमृत' खोलेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि 'अमृत' आउटलेट से करीब 20 करोड़ रू. की दवाइयां बिकी हैं, उसमें रोगियों को लगभग सात करोड़ रुपये देने पड़े हैं, यानी रोगियों को 13 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। हमारी कोशिश है कि हम इन्हें ज्यादा से ज्यादा खोलें। हम ने स्टेट के सभी मेडिकल कॉलेजेज और स्टेट के हॉस्पिटल्स को कहा है कि, please provide us place. We are ready to open 300 AMRIT outlets at this point of time. जैसे-जैसे जगह और जगह मिलेगी, वैसे-वैसे हम इन्हें खोलेंगे।

SHRI A. ANWHAR RAAJHAA: Thank you, Madam. India is the largest democracy in the world and its human resource is its prime wealth. But the Indians are genetically liable to get heart diseases. Only rich people can afford to buy costly stents from the market. Though the Prime Minister's Fund is awarded to a few common men, the same is not sufficient for completing the treatment. Mindful of such things, the former President A.P.J. Abdul Kalam and Dr. B. Somaraju jointly invented the Kalam-Raju Stent way back in 1994 costing about Rs.7,000.

As per the latest statistics, there are 45 million heart patients with Coronary Artillery Diseases in India. Of which, 14 million are urban youths and 16 million are rural youths who want the stents for survival. Scientific achievements will be beneficial only when they reach the common man. Taking new innovation in science to the public is the responsibility of the Government.

At this juncture, why should not the Union Government come forward to obtain patent rates for these stents and undertake its mass production for free of cost treatment of all the heart patients in our country?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA : Madam, two initiatives have been taken in this regard. First is that we have fixed the ceiling prices of stents in CGHS. In CGHS, the maximum price for drug eluting stent is Rs.23,000; bare metal cobalt-chromium including quoted and other stent is of Rs.12,000; bare metal non-coronary vascular stent is of Rs.10,000 and bare metal stainless steel coronary stent is of Rs.10,000. It is because of this ceiling of prices in CGHS, the rates have come down.

Now, when we have brought it in the National List of Essential Medicines and after the NPPA deliberating on it, certainly the stent prices are going to come down. With opening of the AMRIT shops, its prices have reduced by 73 per cent, 76 per cent, 75 per cent and 77 per cent in respect of different companies. It is because of the AMRIT shops that the prices have come down and we are going very fast in this direction. The more we open such shops, the more the prices are going to come down.

श्री गोपाल शेट्टी: अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है। हमारे देश को बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों पर रोकथाम लगाने में सफलता मिली है, लेकिन आज कल हार्ट के आपरेशन और घुटनों के आपरेशन में मुम्बई जैसे शहर में 20 लाख रुपए से 25 लाख रुपए अंडर दि टेबल लिये जाते हैं। मैं मंत्री जी को आने वाले दिनों में इन डाक्टरों के नाम भी देना चाहूंगा। मैं इतने बड़े पवित्र मंदिर में ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं।

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या कोई नया मैकेनिज्म सैटअप करेंगे, जिसमें सामान्य लोगों की बड़ी-बड़ी बीमारियों का इलाज आसानी से सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पतालों में भी हो सके?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से सभी को स्पष्ट करना चाहता हूं कि क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में भारत सरकार का काम है, टेक्निकल सपोर्ट करना, फाइनेंशियल सपोर्ट करना, रेग्यूलेट करना और सर्विलेंस रखना। क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को एक मॉडल एक्ट बनाकर हमने राज्यों को दिया है। It is for the States to adhere to it and

adopt it. अगर राज्य इसे अडॉप्ट करते हैं, तो क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में ये सभी प्रोविजन्स किए गए हैं, जिनके तहत कोई चीज अंडर दि टेबल नहीं हो सकती है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश सरकारों से निवेदन करूंगा कि क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लागू करें।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 382, श्री दुष्यंत चौटाला।

आज सत्र के आखिरी दिन आपका प्रश्न आ गया है।

(Q.382)

SHRI DUSHYANT CHAUTALA: Hon. Madam, according to the 20th Report of the Standing Committee on Defence, for last eight years the Committee were baffled to find that as many as 87 accidents have taken place which work out to be more than 10 accidents per year and in which 75 lives are lost. The data is of a period before May, 2016. The Committee, on one hand, finds that our Services are short of trained manpower and on the other hand, we are losing a large number of manpower in such kind of incidents. We have recently seen an accident which took place in the Bay of Bengal where an AN-32, with 29 officers and technical support members, has gone missing.

On the one hand, the Committee says that we have to make our Air Force to be an accident-free zone and on the other hand, the Air Force's senior Air Marshall states that we are not equipped with adequate manpower as well as our squadron strength, which was supposed to be 42, is at 33. What are the steps that the Indian Armed Forces and the Ministry of Defence, after such words being used by the Committee, taken to make our Indian Forces an accident-free zone?

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Madam, through you, I would like to inform the hon. Member, since he is talking about a recent accident, that from 2007 to 2016, 95 category I accidents have taken place, but when you compare these two years with the previous almost nine years, you will find that there was no accident in previous two years, but then barring this AN-32 incident where the plane is missing, there were comparatively few casualties. I would like to state that this is because out of 95 category I accidents, 47 accidents are involving the MiGs. Hon. Member is right because 11 fighter squadrons are equipped with M-21 and M-27 MiG aircraft, but then, these are going to retire in years to come.

We have addressed this challenged by speeding up the procurement of other things. They have planned induction of SU-30 MKI, Light Combat Aircraft – LCA, Rafale aircraft, very heavy transport aircraft, special operation aircraft,

attack helicopter, heavy lift helicopter and medium lift helicopter. This way, we are going to add not less than 40 fighter squadrons. With this, whatever shortcomings are there, they will definitely be overcome.

Today, we are sure that we have enough trained manpower and enough number of fighter squadrons.

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह हमारे पास रिप्लाई में आया था। मैं चाह रहा था कि वे थोड़ा संक्षेप में देश को बतायें कि जब हमारे पास एक लिमिटेड मैनपावर है। We are still not improving.

माननीय रक्षा मंत्री जी ने राज्य सभा में जवाब देते हुए कहा था that our yearly ratio is the lowest in the country at 0.23 for every 10,000 hours of flight. Internationally, it is 0.023. So, we are ten times higher than what the international standards are.

मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि अप्रैल, 2014 से अगस्त, 2016 तक इंडियन एयरफोर्स में 14 क्रैशिज हुए हैं और उनमें बहुत बड़ी तादाद में हमारी डिफैंस फोर्सेज के कर्मचारियों की जानें गई, मगर आज तक किसी भी अफसर या कर्मचारी को, जिनकी इन एक्सिडेन्टस में जान जाती है, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया।

महोदया, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इस संबंध में कोई कदम उठायेगी, क्योंकि वे भी हमारे देश के सैनिक, जवान और अफसर हैं, जो इस देश की सेवा के दौरान ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, परंतु उस कारण उनकी जान जाती है तो क्या भारत सरकार उन्हें भी शहीद का दर्जा देने का काम करेगी और उनके परिवारों की मदद करने का काम करेगी?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI MANOHAR PARRIKAR): Madam, I would like to inform the hon. Member that except this AN-32 incident, in the last 24 months, we have not lost a single life. So, whatever crisis has taken place, it has not resulted in loss of life. The figure he quoted is for the earlier years.

Secondly, he said about 0.112 international figure. It is not an international figure; it is the figure mostly of US Air Force which he is quoting.

SHRI DUSHYANT CHAUTALA : It was quoted by you in Rajya Sabha that we have lost lives in Dornier also.

श्री मनोहर पर्रिकर : डोर्नियर प्लेन कोस्ट गार्ड का है और डिफैंस फोर्सेज में कोस्ट गार्ड नहीं आते। एयरफोर्स का जो क्रैश हुआ है, एयरफोर्स के क्रैशिज़ में पिछले दो वर्ष में सिर्फ ए.एन. - 32 को छोड़ कर एक भी लाइफ नहीं गई है। This figure of 0.112 per 10000 hrs of the USA for the year 2015 is definitely better than our figure. Our figure was 0.29, 0.40 and 0.22 for the years 2013-14, 2014-15 and 2015-16 respectively; so, we have brought down our figure. Secondly, the US Air Force has a better figure and it is because their flying hours are much longer. They do flying for ten hours and hence the resultant risk of accidents reduces. The normal accident risks are more at take-off and landing times. So, they keep flying for longer hours. We do not have that kind of requirement, but they do have that kind of requirement. These two factors definitely make a difference. We are going in for better maintenance of the aircraft. I can assure the Member that unless an aircraft is in a position to fly, it is never allowed to be flown.

श्री दुष्यंत चौटाला: सर, एक्सिडेंट से मरने वाली बात का आपने जवाब नहीं दिया? ...(व्यवधान)

श्री मनोहर पर्रिकर : जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, उसके हिसाब से जो उसमें आ जाते हैं, उनको बैनीफिट मिलता है।

DR. M. THAMBIDURAI: Madam Speaker, in his first supplementary, Shri Dushyant Chautala raised a question regarding the aircraft which flew from Tambaram to Andaman carrying 29 officers. In this connection, the Minister also gave a statement in the House. What has happened after that? What is the position of the investigation and search operations conducted by the Ministry? Have they got any clue? What is the fate of those 29 officers who went missing? Have you got any confirmation or have you found out what had happened to them? What is the position? Their family members are really concerned about them. It is a serious thing that had happened in Chennai. Therefore, through you, Madam, I request the Minister to tell us what the actual position is in regard to that accident which had happened on that day.

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Madam, through you, I would like to inform the House that this unfortunate incident had occurred on 22nd July. For your information, I may tell you that the Indian Air Force operates a courier service from Tambaram to Port Blair thrice a week. This particular flight departed on 22nd July at 08.30 a.m. After its departure, when it went South East towards Port Blair, around 250 kilometres away from Chennai, suddenly, we noticed on radar a thundershower cloud or a bad patch. This particular aircraft is equipped with the weather avoidance radar. The radar guided the flight to deviate to the right sight to avoid it. Accordingly, when the flight deviated to the right side, suddenly, it disappeared and we lost contact with it on the radar. Immediately, a massive rescue operation was ordered.

Till now, a total of 200 sorties/898 hours have been flown. The air assets deployed included six P8I aircraft, two Dornier Do-228 aircraft, six helicopters of Indian Navy, three AN-32 aircraft, three C-130 aircraft, two Avro aircraft, two Mi-17 V5 helicopters, and six Dornier Do-228 aircraft of the Indian Coast Guard. In addition to that, one Bombardier Global 5000 aircraft was also deployed. Further, 18 Indian Navy, eight Indian Coast Guard ships and one submarine have been deployed in the search area. All merchant vessels passing through the SAR area as well as local fishing communities were asked to report any sighting of survivors/debris.

As a result of coordinated surface and air search, areas of three oil slicks, 24 transmission intercepts and 30 floating objects have been found. Those were thoroughly investigated by ships and aircraft without any concrete evidence emerging with respect to the missing IAF AN-32 aircraft. Unfortunately, we did not get any clue so far.

DR. M. THAMBIDURAI: I would like to know whether they are surviving or not. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: How can they? They cannot say.

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Looking at this kind of mishaps, this looks like a crash. At that particular level, it was at 3.5 kilometres, that is, 3500 metres. At that level, it becomes very difficult even for the submarine to locate. But then the search operation is going on.

I could also cite other examples of this kind. You may remember there was one Malaysian aircraft MH 370. That happened in the Indian Ocean some one and a half years back. Search is still going on. But they could not locate the whereabouts of that. There was other incident of the Air France aircraft in the Atlantic Ocean, which was found after two years. In a similar case, CG DO 921 went missing over the Bay of Bengal on 8th June, 2015. This aircraft was located after a duration of 34 days. As far as survival is concerned, it is unlikely after so many days. But then, relatives and immediate family members were informed. Officers are personally meeting them and they are informing them on a day-to-day basis. We are doing our level best. Search is going on. We are not going to stop the search at any time till we get some evidence.

SHRI THOTA NARASIMHAM: Madam, what are the reasons for the recent crash of Russian aircraft AN-32? Just now, the hon. Deputy Speaker and Shri Dushyant Chautalaji had asked about it. The Indian Air Force light military transport aircraft was flying from Chennai to Port Blair on 22nd July of this year. There were 29 military personnel on board including nine personnel from Vizag. Is it a fact that three snags were found in the same aircraft in the same month? Is it also a fact that MIG-21 aircraft which constitutes a major part of the Air Force, is referred as flying offence? If so, how is the Government plan to replace them? When is the Government considering indigenous production of combat aircraft as a better alternative to that of imports? Why are no other indigenous combat planes developed except Tejas, the Light Combat Aircraft, to meet the diversified requirements of the Indian Air Force? Is there any future plan in this regard?

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Madam, I would like to inform the hon. Member one thing. I understand his concern. Out of 95 category-I accidents, in 41

accidents MIG-21 was involved. But, as we are aware, there is an initiative of the Prime Minister called 'Make in India'. Under this, we are going for the indigenous production in Defence. Even in the fighter squadron, we are doing indigenous production in the case of Light Combat Aircraft from the Hindustan Aeronautics Limited. We are getting those kinds of fighter squadrons. Besides that, I have already mentioned that capital procurement procedure is going on regarding the Rafale induction, Sukhoi 30-MKI and a host of others. Very soon, 40 fighter squadrons will be added. We are sure about our strength in the sky. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Q. No. 383. Shri Kapil Moreshwar Patil.

… (*Interruptions*)

SHRI DINESH TRIVEDI: Madam, I am on a point of order. ... *.

* Not recorded.

(Q. 383)

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील : माननीय अध्यक्ष महोदया, कालेज और स्कूलों के छात्रों के लिए एन.सी.सी. ट्रेनिंग अनिवार्य करने के बारे में मेरा सवाल था। मुझे जो जवाब दिया गया है, उसमें कहा गया है कि हमारे पास मानव शक्ति और संसाधनों की कमी है, जिसकी वजह से हम यह कर नहीं सकते हैं। मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से गुज़ारिश है कि अमेरिका में, रूस में और इस्त्राइल में एन.सी.सी. ट्रेनिंग और सैन्य ट्रेनिंग सभी सिविलियन्स के लिए अनिवार्य है, इसलिए उनमें अपने देश के प्रति एक जज़्बा रहता है। हमारे युवाओं को अगर स्कूलों और कालेजों में एन.सी.सी. का प्रशिक्षण दिया जाए, तो उनमें भी देश के प्रति एक जज़्बा हो सकता है। आप कल का एक उदाहरण देखें तो कल दिल्ली में एक एक्सीडैंट हुआ। वहाँ एक आदमी 90 मिनट तक तड़पता रहा, लेकिन उसकी किसी ने मदद नहीं की और उसकी मृत्यु हो गई। अगर वहाँ से कोई एन.सी.सी. का ट्रेनिंग लिया हुआ आदमी गुज़रता, तो वह सौ टका उसकी हैल्प करता, उसे हॉस्पिटल में पहुँचाता। इससे उसकी जान बच सकती थी।

मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना है कि आने वाले दिनों में मानव शक्ति और संसाधनों को पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय के बजट में क्या आप कुछ ऐसा प्रावधान करने के बारे में सोच रहे हैं कि स्कूलों और कालेजों में युवाओं को एन.सी.सी. की ट्रेनिंग मिले?

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Madam Speaker, through you I would like to inform the hon. Member that as far as Israel is concerned there is compulsory military training and participation. In US, I do not think it is compulsory any more and I am not aware of Russia in terms of compulsions. But in India if we make NCC compulsory, the total number of potential cadets who we will require to train probably will exceed four crore. Today we are doing around 13 lakh cadets and that is likely to increase to 14 lakh cadets. While I agree with the hon. Member's feeling that NCC induces patriotism and discipline among people, I think it is not necessary that compassion for a person lying bleeding on the road should necessarily come from NCC, it can come also from family culture and background and training at home. However, we are examining the possibility of introducing package NCC programmes for schools which should take care of

around 15 lakh additional students. We can increase the number but I cannot consider making it compulsory because we do not have that infrastructure.

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील: माननीय अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र में एन.सी.सी. की 61 यूनिट्स हैं, परंतु ये वहाँ के लिए कम हैं। इनके ट्रेनिंग सैन्टर्स को अत्याधुनिक करना भी ज़रूरी है। एन.सी.सी. कैडेट्स अपनी ट्रेनिंग ठीक से कर सकें, क्या इसके लिए सरकार यह विचार कर रही है कि महाराष्ट्र सरकार को इस प्रयोजन हेतु वित्तीय सहायता मुहैया कराए, ताकि यूनिट्स को अपने ट्रेनिंग सैंटर्स और सभी एन.सी.सी. कैडेट्स को सही ढंग से ट्रेनिंग दी जा सके?

श्री मनोहर पर्रिकर : माननीय सदस्य मुझे लिखकर दे दें कि सरकार से क्या चाहिए, तो we can definitely consider improving further. मैं पर्सनली इस पर ध्यान दे रहा हूँ कि एन.सी.सी. की फैसिलिटीज़ और ट्रेनिंग में सुधार आ जाए।

श्री कौशलेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि लघु ईकाई के रूप में एन.सी.सी. को माना जाता है। मेरा माननीय मंत्री जी से सीधा सवाल है कि आज हमारे देश के बच्चे और बच्चियों को एन.सी.सी. की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उसमें आज भी हमारे बच्चे और बच्चियों को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय में जो भी वैकेंसी होती है, क्या एन.सी.सी. कैंडटों को उसमें बहाल करने का कोई विचार है?

श्री मनोहर पर्रिकर : उसमें एन.सी.सी. के लिए ज्यादा गुण रहते हैं। मेरे हिसाब से, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक रिक्रूटमेंट के एराउंड 6-7% में एन.सी.सी. वाले रहते हैं। इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। That is what I remember.

HON. SPEAKER: Q. 384.

Shri Ramesh Bidhuri - Not Present.

Now, the hon. Minister.

(Q. 384)

HON. SPEAKER: Shri Rattan Lal Kataria.

श्री रत्न लाल कटारिया: महोदया, पहले तो मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने फाइनैंशिएल इन्क्लूज़न के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं देश के अन्दर लागू की हैं, जिनसे रोज़गार के अवसर बढ़ रहे हैं। आदरणीय मंत्री जी ने अपने इस प्रश्न के उत्तर में बताया है कि स्टार्ट-अप्स और स्टैण्ड-अप्स के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रीयल कमेटी का गठन हुआ है।

महोदया, प्रधान मंत्री जी के 'स्टार्ट-अप इंडिया', 'स्टैण्ड-अप इंडिया' कार्यक्रम के शुरू होने के पश्चात् हिन्दुस्तान के दलितों में और महिलाओं में विशेष उमंग आई है और उनका एन्टरप्रेन्योरशिप की ओर रूझान बढ़ा है। उस मीटिंग के अंदर इसकी समीक्षा की गयी है। चूंकि यह स्कीम जनवरी, 2016 में शुरू हुई है तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह रूझान किस तरह का है? किस तरह से बैंकों ने दलितों को और महिलाओं को इस स्कीम के बेनीफिट उठाने की दिशा में कदम उठाए हैं? जिस प्रकार से प्रधान मंत्री जी ने विक्की में जाकर दलित एन्टरप्रेन्योरशिप का हौसला बढ़ाया था, तो इस प्रकार के कितने कदम मंत्रालय की ओर से उठाए गए हैं, मैं यह जानना चाहूंगा।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : स्पीकर महोदया, माननीय प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त, 2015 को इंडिपेंडेंस डे पर 'स्टार्ट-अप इंडिया', 'स्टैण्ड-अप इंडिया' इनिशिएटिव का उल्लेख किया था। माननीय सदस्य ने जो पूछा है, मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि स्टार्ट-अप्स का मतलब बेसिकली है - The concept is working towards innovation, development, deployment or commercialization of new products, processes or services driven by technology or intellectual property.

इन्होंने स्टैण्ड-अप के बारे में पूछा है कि इसमें दलित लोगों का क्या रूझान है। मैं आपके माध्यम से इन्हें बताना चाहता हूं कि स्टैण्ड-अप इंडिया में अभी तक प्रधान मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि इस देश में 1.25 लाख बैंकों की ब्रांचेज हैं। एक एस.सी., एस.टी. एंटरप्रेन्योर को और एक महिला एन्टरप्रेन्योर को हर ब्रांच लोन दे और उस लोन की जो सीमा है, वह दस लाख रुपए से लेकर एक करोड़ रुपए तक है। अब तक जो इसमें प्रोपोजल्स आए हैं, उनकी संख्या 800 से ऊपर है और इसके लिए बहुत अच्छा रूझान है।

DR. SHASHI THAROOR: Hon. Speaker Madam, I am sure the hon. Finance Minister shares my concern that investment in Indian Start-ups has declined in the first quarter of 2016 according to the KPMG Report. It seems that with mounting investor hesitation and concerns of over-valuation, we have had deals slipping by four per cent and funding falling by 24 per cent in the first quarter of this year. I am sure the hon. Minister will agree that we need to see more capital coming up into Startups. The Prime Minister has made a big initiative of 'Start-up India.' Smart capital is required so that we can get both experience and access to our Start-ups here. But in his Budget speech, the hon. Minister only gave an assurance that there would be no tax on Startups in the first couple of years. But as I pointed out in the past, no Startups are going to make profits in the first couple of years.

We need to give tax incentives and tax breaks to the investors, not to the angel investors but to those who bring in smart capital. My question to the hon. Minister of Finance is this. Given that you have mentioned that the Government has approved funds for start-ups with Rs. 10,000 crore of government money, rather than spending the taxpayers' money why do we not give incentives to investors so that they will get to pay less tax in order to fund start-ups in our country and thereby help the larger objective of 'Start-up India'?

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARUN JAITLEY): In the entire package of tax concessions which is a part of the start-up package for instance there is an exemption from payment of capital gains tax if you liquidate a capital asset in order to invest in a start-up. That is also part of the package itself. That in itself is an incentive to a potential investor.

With regard to those who invest – I agree with the hon. Member that since it is an innovation, it is a hit and trial – there are start-ups which will fail, there are start-ups, which will have to exit, and there are start-ups which will succeed and their valuations will go up phenomenally. Therefore, some kind of flexibility and elasticity has been given to them. They can choose a block of three years out of the five years in which they are entitled to an exemption from payment of taxes and that amount of flexibility is a apart of the tax concession package given to the start-ups.

SHRI K.C. VENUGOPAL: Thank you very much, Madam Speaker. This is related to the safety of investors. With your permission, I have already raised the issue of high-tech robberies in ATMs which have happened in Kerala over so many days in Thiruvananthapuram and Alappuzha. Four persons have already been arrested but the robberies are still continuing. Actually, the incident is an eye-opener to lacunae in security measures at ATMs. The chip-based ATM cards can be sensed by sitting in a car outside the ATM. The RBI should adopt updated technology and uniform safety standards to address the concern of the people. I would like to ask a supplementary question whether the Government is taking this issue seriously and what action has been taken or is going to be taken.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, even though this question is not concerned with the main Question, I quite appreciate the concern of the hon. Member. As technological advancements take place, the number of those who misuse the technology and try to pierce through the technology also increases. It is not only in the context of the ATMs in Kerala that he has mentioned but recently an incident has also come to notice where an effort made to hack into the system of one of the public sector banks. Fortunately, it was detected and any possible damage was saved. Therefore, this has highlighted the issue. Both the RBI and the Government, and the bank have taken it very seriously. Therefore, the technological firewalls to be created around the technology system of the banks is being further strengthened. The banking system is seriously looking into this

whole issue. They are fully seized of it. If those systems could be hacked, the entire system of financial security will get threatened.

(Q. 385)

कुँवर हरिवंश सिंह: अध्यक्ष महोदया, देश में इंस्टेंट नूडल्स के कई ब्रांड्स एवं इसके अतिरिक्त कई प्रकार के खाद्य पदार्थों जैसे बर्गर, पिज्जा इत्यादि में एमएसजी, मोनो सोडियम ग्लूटामेट का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक है। सरकार ने शाकाहारी खाद्य पदार्थों के पैकेट पर हरी बिंदी तथा मांसाहारी खाद्य पदार्थों के पैकेट पर लाल बिंदी का लेबल लगाना अनिवार्य किया है। जिस प्रकार से सिगरेट के पैकेट एवं अन्य तम्बाकू के उत्पादों पर बड़ी-बड़ी स्वास्थ्य चेतावनी होती है, उसी की तर्ज पर क्या सरकार एमएसजी युक्त खाद्य पदार्थों के पैकेट पर विशिष्ट लेबलिंग की व्यवस्था को अपनाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जैसी चिंता जाहिर की है, भारतीय खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम द्वारा वर्ष 2006 में इस कानून को बनाया गया था, इसके उपरान्त वर्ष 2008 में पहली बार खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रधिकरण की स्थापना हुई और वर्ष 2011 में इसे कानूनी रूप से लागू कर दिया गया। इसके अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं, उनको इसके अंदर शामिल किया गया है। मुझे लगता है कि यह कानून अपने ढंग से प्रभावी तरीके से आगे कार्रवाई करेगा।

कुँवर हरिवंश सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की एकमात्र जिम्मेदारी दिशा-निर्देश जारी कर खानापूर्ति करना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि राज्य सरकारों द्वारा उन दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करने हेतु उनके पास पर्याप्त मात्रा में मानव शक्ति, उन्नत प्रयोगशालाएं, बजट एवं अन्य साधन हैं या नहीं। राज्य सरकारों के पास इन संसाधनों की भारी कमी है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों, विशेषकर उत्तर प्रदेश को अधिक वित्तीय सहायता देने पर विचार करेगी? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने विशेषकर उत्तर प्रदेश के बारे में चिन्ता जाहिर की है। हम समय-समय पर इस पर कार्रवाई करते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग की स्थापना करना इसका मूल लक्ष्य है। मुझे लगता है कि हम इस बारे में राज्य सरकारों की जितनी मदद कर सकते हैं, उसकी पूरी कोशिश होती है। राज्य सरकारों को इस बारे में चिन्ता करनी चाहिए, क्योंकि यह राज्य से संबंधित विषय है।

SHRI DUSHYANT SINGH: Thank you Speaker Ji for allowing me to ask a supplementary. The Food Safety and Standard Authority was formed in 2006. It

basically regulates the manufacture, storage and distribution of food articles. All of us in this House drink milk. Madam, 68 per cent of the milk nowadays is adulterated. It is being spoiled by adding either caustic soda, glucose or other adulterants. The hon. Minister for Science and Technology is also present in the House today. He had stated in reply to earlier Question that the Government has undertaken a pilot study to test the milk products. Every time such Questions are asked and the reply given is that food standards are managed by the States and the research and development is done by the Centre. I would like to know from the Minister whether the Ministry of Health is working with the Ministry of Science and Technology to study the milk products. A pilot scheme involving GPS-based technology to test the milk products has been undertaken in Pilani, Rajasthan. Such testing teams have been sent to other parts of India. Is the Ministry thinking of taking up this GPS-based technology to test other food products also?

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : अध्यक्ष महोदया, हमारा काम मानक तैयार करना है, लेकिन राज्य सरकारें इसका ठीक से पालन करें, यह चिन्ता उन्हें करनी चाहिए। जहां तक लैबों का सवाल है, इस समय देश में अलग-अलग श्रेणी, जैसे प्राइवेट आदि मिलाकर 198 लैब्स काम कर रही हैं। इस मानक के आधार पर राज्य सरकारों को ध्यान रखना चाहिए।

श्री धर्म वीर गांधी: अध्यक्ष महोदया, मै मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि न सिर्फ खाद्य पदार्थों के मामले में, बल्कि दवाइयों के मामले में भी हमें वैज्ञानिक पहुंच बनानी चाहिए। आज एविडैंस बेस्ड मैडिसन का युग है। हर नया मॉलिक्यूल जो मार्किट में आता है, वह बहुत ट्रॉयल के बाद आता है - एनिमल ट्रॉयल्स होते हैं, थ्री स्टेज ह्यूमन ट्रॉयल्स होते हैं। आज बहुत से आचार्यों और बाबाओं के प्रोडक्ट्स मार्किट में धड़ाधड़ आ रहे हैं। क्या वे उन मापदंडों पर खरे उतरते हैं? जब तक उन सभी प्रोडक्ट्स का ह्यूमन ट्रॉयल और एनिमल ट्रॉयल का प्रमाण नहीं मिलता, वैज्ञानिक आधार नहीं मिलता, तब तक उन सबको हटाना चाहिए, ताकि लोगों को सुरक्षित दवाइयां मिल सकें।

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : अध्यक्ष महोदया, मैंने बार-बार कहा है और सरकार की चिन्ता है कि जो मानक तैयार किए जाते हैं, अगर कोई भी प्रोडक्ट उन मानकों के अहित में होता है तो उस पर कार्रवाई होती है। यह एक पक्ष है, इस पर हम हमेशा कार्रवाई करते हैं। अगर मानक के अगेंस्ट मार्केट में दवा आती है तो सरकार उस पर निश्चित रूप से गंभीरता से विचार करती है।

SHRIMATI R. VANAROJA: Madam, I thank you for allowing me to ask a supplementary question.

In the recent past, there had been reports that many multinational companies were taking advantage of loopholes in the FSSAI guidelines and they were able to overcome the legal battles also. Therefore, I would like to know from the hon. Minister the steps taken by the Government to make FSSAI guidelines more stringent.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Madam, improving the standards of the product and testing facilities is a continuous process. Keeping that factor in view, the FSSAI has come up with new standards which are now in public domain. Now it is for us to comment on them. These new standards have got issues related to indication about ingredients, about quality, safety parameters and about safety of the raw material. These three issues have been taken into consideration. Now it is in the public domain. We are trying to follow the standards accordingly.

We are also trying to see that the protocol of processing is also taken into consideration as far as standards are concerned. So, all this is being done. The multinationals or national companies are adhering to it.

The new standards are in public domain. After we get the comments of the public, we will be notifying them and we will see that they are followed accordingly.

(Q. 386)

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, ईडी का मामला कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा पकड़ा गया, इसकी सीबीआई द्वारा जांच भी हुई। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ईडी का केस रजिस्टर हुआ है या नहीं?

श्री संतोष कुमार गंगवार : हमारी सरकार आने के बाद पूरी सक्रियता के साथ कदम उठाया था। पहली कैबिनेट बैठक में इस ओर प्रभावी कदम उठाने का काम किया था। ईडी जिस तरीके से मामले को देखता है, फेमा के तहत विदेशी मुद्रा विनिमय के आवागमन में अनियमितता बरती जाती है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। पिछले तीन वर्षों में 2321 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और सवा दो सौ करोड़ की पैनल्टी भी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट के अंतर्गत ऐसे सारे मामलों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अगर माननीय सदस्य को कहीं कोई बात नजर आती है तो उस पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, के.आर.मंगलम स्कूल के वरीय पदाधिकारीगणों का इन्वोल्मेंट है। हमने इसी विषय पर प्रश्न किया था। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं।

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अगर वह कोई स्पेसिफिक जानकारी चाहते हैं तो उसे बाद में देंगे। मैंने प्रारंभ में कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद से ही इस मामले में बहुत सतर्क है। पहली कैबिनेट बैठक में ही एसआईटी का गठन किया गया और उसके हिसाब से प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद अगर माननीय सदस्य जी को कोई विशेष जानकारी चाहिए तो हम उसे बाद में अवगत कराएंगे।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I want to know whether DRI has unearthed Rs. 2240 crore relating to banking hawala scam that has happened in Mumbai and whether six public sector banks are involved in generation of this fund which was illegally remitted overseas. How could this happen when many firewalls have been created in the last two years? Despite that, two major public sector banks, namely, Punjab National Bank and Canara Bank and four other banks are involved including some branches through which this hawala had taken place. What steps have been taken in this regard, whether anybody has been apprehended, whether that money has been recovered and despite all these firewalls, how could this happen?

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARUN JAITLEY): As far as this specific case is concerned which the Member or any other Member wants to know, if he can write to me, I can find out the details of the specific case, the stage of investigation and the action taken against the concerned public servants and I will certainly intimate it to the hon. Member.

(Q. 387)

SHRI P.K. BIJU : Madam, on 29/9/2014, we have started the National AYUSH Mission (NAM) for envisaging better access to AYUSH services, strengthening of AYUSH educational institutions, facilitate the enforcement of quality control of Ayurveda, Siddha and Unani and Homoeopathy drugs and sustainable availability of raw materials for ASU and H drugs in the States and UTs during the 12th Plan.

We have started an Institute in 1970s in Kerala which happened to be in my constituency. Panchakarma Institute was established under the direct involvement of AYUSH. I have sent many letters to AYUSH for strengthening that institution. Now that institution is in a difficult condition. Doctors and medicines are not available.

I would request the hon. Minister to save and strengthen that institution under NAM which is meant to strengthen the educational institutions and hospitals which are under the control of AYUSH.

श्री श्रीपाद येसो नाईक : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि स्ट्रैंथनिंग करने के लिए एग्जेक्टली क्या-क्या चाहिए। प्रपोजल राज्य सरकार के जरिए आयुष मिनिस्ट्री को भेजना होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रपोजल तो राज्य सरकार से आता है, इसमें 40 परसेंट इन्वेस्टमेंट राज्य सरकार करती है और 60 परसेंट इन्वेस्टमेंट आयुष मंत्रालय करता है।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि स्ट्रैंथनिंग के प्रपोजल में स्ट्रैंथनिंग के लिए 75 लाख रुपया देते हैं, जो अस्पताल पुराना होता है। मैं माननीय सदस्य से रिक्वेस्ट करता हूं यदि आपने प्रपोजल नहीं भेजा है तो भेजने की कृपा करें।

SHRI P.K. BIJU : Madam, this is a Central Institution. I think, Central Institutions are under the full control of the Central Government. I hope the hon. Minister will look into this aspect.

Kerala is God's own country. A lot of tourists come there across the border mainly for Ayurvedic treatment. We are in a difficult condition to collect Ayurvedic medicine. We are importing some medicines but I want to know from

the hon. Minister whether he will have a Mission to give some assistance to the States for improving Ayurvedic medicinal plantations.

12.00 hours

श्री श्रीपाद येसो नाईक : अध्यक्ष महोदया, नैशनल आयुष मिशन में प्लांटेशन की एक स्कीम है। जैसा मैंने कहा कि राज्य सरकार को इसमें 40 परसेंट इन्वेस्ट करना होता है, जबकि 60 परसेंट आयुष इन्वेस्ट करता है। सैंट्रली सैक्टर स्कीम्स में हम राज्य सरकार को प्लांटेशन के लिए 100 परसेंट पैसा देते हैं। इसी तरह एनजीओज को भी 100 परसेंट पैसा देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले दस सालों में आयुष, आयुर्वेद या बाकी सभी पैथीज में रॉ मैटीरियल चाहिए, तो वह पेड़ों से ही मिलता है। इसलिए मैं सबसे रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि वे सैंट्रली सैक्टर स्कीम और सैंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम के तहत हमारी स्कीम अवेल करें और हमारा रॉ मैटीरियल बढ़ाने के लिए ट्री प्लांटेशन करें।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, धर्मेन्द्र यादव, सुदीप बंदोपाध्याय और के.सी.वेणुगोपाल से विभिन्न विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, परंतु इनके लिए सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालना अनिवार्य नहीं है। ये मामले अन्य अवसरों पर उठाए जा सकते हैं।

इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अनुमति प्रदान नहीं की है।

12.02 hours

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, the House will take up Papers to be Laid on the Table.

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to lay on the Table a copy of the Medium term Expenditure Framework Statement for 2016-2017 (Hindi and English versions) under section 3 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003.

[Placed in Library, See No. LT 5170/16/16]

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): I beg to lay on the Table a copy of the Statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Annual Report and Audited Account of the Indian Red Cross Society, New Delhi, for the year 2014-2015 within the stipulated period of nine months after the close of the accounting year.

[Placed in Library, See No. LT 5171/16/16]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Limited, Almora, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Limited, Almora, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 5172/16/16]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5173/16/16]

(2) 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5174/16/16]

(3) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्त सलाहकार) विनियम, 2016 जो 17 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए 12 /आर जी एल/139/1 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 5175/16/16]

(4) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 की उपधारा (5) के अंतर्गत वर्ष 2014-2015 के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(5) उपयुर्क्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5176/16/16]

(6) डिपोसिट इंश्योरेंस एण्ड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, मुम्बई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[Placed in Library, See No. LT 5177/16/16]

(7) (एक) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5178/16/16]

(8) आईडीबीआई बैक, मुम्बई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[Placed in Library, See No. LT 5179/16/16]

(9) बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथासंशोधित भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, की धारा 40 की उपधारा (4) तथा बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथासंशोधित भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण और कार्यकलापों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[Placed in Library, See No. LT 5180/16/16]

(10) (एक) लाईफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लाईफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5181/16/16]

(11) लाईफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के 46वां मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 5182/16/16]

(12) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1641(अ) जो 4 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल राज्य में एर्नाकुलम में ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5183/16/16]

(13) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2016, जो 17 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 502(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (5वां संशोधन) नियम, 2016, जो 15 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1101(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (8वां संशोधन) नियम, 2016, जो 23 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1206(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 1948 (अ) जो 02 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा

जिसके द्वारा 20 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 709 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) आयकर (16वां संशोधन) नियम, 2016, जो 22 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2179(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) आयकर (19वां संशोधन) नियम, 2016, जो 28 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2226(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 5184/16/16]

(14) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 727(अ) जो 26 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित सनसेट समीक्षा जांच के परिणाम आने तक उसमें उल्लिखत कतिपय रबर कमिकल्स के आयात पर लगाए गए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को और एक वर्ष की अवधि तक अर्थात् 27 जुलाई, 2017 जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 5185/16/16]

(15) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 524(अ) जो 17 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थी तथा जिनका आशय द्विपक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा सुगम बनाए जाने वाली धार्मिक तीर्थयात्रा के संबंध में विनिर्दिष्ट संगठनों द्वारा 1.7.2012 से 19.08.2014 की अवधि के दौरान प्रदान की गई सेवा, जब उस अवधि के संबंध में उक्त सेवा पर सेवा कर का संदाय किए जाने का प्रचालन नहीं था, के संबंध में वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ख के अंतर्गत देय सेवाकर में छूट प्रदान करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 5186/16/16]

(16) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखत वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) वर्ष 2015-16 के लिए इलाहाबाद बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 5187/16/16]

(दो) वर्ष 2015-16 के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 5188/16/16]

(तीन) वर्ष 2015-16 के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 5189/16/16]

(चार) वर्ष 2015-16 के लिए देना बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 5190/16/16]

(पांच) वर्ष 2015-16 के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 5191/16/16]

(छह) वर्ष 2015-16 के लिए पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 5192/16/16]

(सात) वर्ष 2015-16 के लिए यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 5193/16/16]

(आठ) वर्ष 2015-16 के लिए यूको बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 5194/16/16]

(नौ) वर्ष 2015-16 के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 5195/16/16]

(दस) वर्ष 2015-16 के लिए केनरा बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 5196/16/16]

(ग्यारह) वर्ष 2015-16 के लिए कार्पोरेशन बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 5197/16/16]

(बारह) वर्ष 2015-16 के लिए इंडियन बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 5198/16/16]

(तेरह) वर्ष 2015-16 के लिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 5199/16/16]

(चौदह) वर्ष 2015-16 के लिए सिंडिकेट बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 5200/16/16]

(पंद्रह) वर्ष 2015-16 के लिए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 5201/16/16]

(सोलह) वर्ष 2015-16 के लिए विजया बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 5202/16/16]

(सत्रह) वर्ष 2015-16 के लिए आंध्रा बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 5203/16/16]

(अठारह) वर्ष 2015-16 के लिए बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 5204/16/16]

(उन्नीस) वर्ष 2015-16 के लिए पंजाब और सिंध बैंक के कार्यकरण तथा कार्यकलापों के बारे में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 5205/16/16]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते): अध्यक्ष महोदया, मैं खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषकों, विष और अवशिष्ट) (संशोधन) विनियम, 2015 जो 12 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 1-91/1/एसपी/ (संदूषक)/एफएसएसआई/2009 में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 12 फरवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या एफ. सं. 1-99/एसपी/ (संदूषक)/ एफएस एस आई/2009 में प्रकाशित हुआ है।

(2) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (केन्द्रीय सलाहकार समिति के कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया) पहला संशोधन विनियम, 2016 जो 29 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.1-61/एफएसएसआई/टीआर बिजनेस सी एसी/रेग/2015 में प्रकाशित हुए थे

(3) खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषकों, विष और अवशिष्ट) तीसरा संशोधन विनियम, 2016 जो 4 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. पी. 15025/264/13-पीए/एफएसएसआई में प्रकाशित हुए थे।

(4) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) दूसरा संशोधन विनियम, 2016 जो 25 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 1-(94) 2015 / अधिसूचना पी एण्ड एल/ईएनफ//एफएसएसआई में प्रकाशित हुए थे।

(5) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) तीसरा संशोधन विनियम, 2016 जो 14 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी. 15-03//ईएनफ/एफएसएसआइ/2014 में प्रकाशित हुए थे।

(6) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) दूसरा संशोधन विनियम, 2016 जो 4 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 03-16/विनिर्दिष्ट खाद्य/अधिसूचना (खाद्य योजक) / एफ एसएसआइ-2014 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 5206/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): On behalf of Shri Kiren Rijiju, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 20 of the Protection of Human Rights Act, 1993:-

(i) Annual Report of the National Human Rights Commission, India, New Delhi, for the year 2012-2013.

(ii) Memorandum of Action Taken on the recommendations contained in the Annual Report of the National Human Rights Commission, India, New Delhi, for the year 2012-2013.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 5207/16/16]

(3) A copy of the Border Security Force, Engineering (Civil) Combatant (Group 'B' posts) Recruitment Amendment Rules, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.761(E) in Gazette of India dated 3rd August, 2016 under sub-section (3) of Section 141 of the Border Security Force Act, 1968.

[Placed in Library, See No. LT 5208/16/16]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी, इम्फाल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इम्फाल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखाओं प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इम्फाल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5209/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Securities and Exchange Board of India, Mumbai, for the year 2014-2015, together with Audit Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 5210/16/16]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992:-

(i) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities by Municipalities) Regulations, 2015 published in Notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2015-16/006 in Gazette of India dated 15th July, 2015.

(ii) The SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements (Third Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2015-16/007 in Gazette of India dated 11th August, 2015.

(iii) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2015-16/008 in Gazette of India dated 14th August, 2015.

(iv) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2015-16/009 in Gazette of India dated 14th August, 2015.

(v) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) (Second Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2015- 16/010 in Gazette of India dated 14th August, 2015.

(vi) The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2015-16/011 in Gazette of India dated 14th August, 2015.

(vii) The SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements)(Fifth Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. SEBI/LAD/NRO/G.N./2015-16/012 in Gazette of India dated 14th August, 2015.

(viii) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 published in Notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2015-16/013 in Gazette of India dated 2nd September, 2015.

(ix) Notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2015-16/014 published in Gazette of India dated 4th September, 2015 renaming "MCX Stock Exchange Limited" as "Metropolitan Stock Exchange of India Limited.

(x) The Securities and Exchange Board of India (Regulatory Fee on Stock Exchanges) (Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2015- 16/015 in Gazette of India dated 8th September, 2015.

(xi) The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2015-16/016 in Gazette of India dated 8th September, 2015.

(xii) The Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. SEBI/AD-NRO/GN-2015-16/017 Sin Gazette of India dated 8th September, 2015.

(xiii) The SEBI (Issue and Capital and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/018 Gazette of India dated 10th September, 2015.

(xiv) Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/019 published in Gazette of India dated 14th September, 2015 regarding renewal of recognition of Metropolitan Stock Exchange of India Limited.

(xv) The Securities and Exchange Board of India (Procedure for Search and Seizure) Repeal Regulations, 2015 published in Notification No. SEBI/LADNRO/GN/2015-16/020 Gazette of India dated 17th September, 2015.

(xvi) The SEBI (Share Based Employee Benefits) (Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. SEBI/LADNRO/GN/2015-16/021 Gazette of India dated 18th September, 2015.

(xvii) Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/022 published in Gazette of India dated 1st October, 2015 regarding renewal of recognition of National Securities Clearing Corporation Limited.

(xviii)Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/023 published in Gazette of India dated 1st October, 2015 regarding renewal of recognition of Indian Clearing Corporation Limited.

(xix) Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/024 published in Gazette of India dated 1st October, 2015 regarding renewal of recognition of MCX-SX Clearing Corporation Limited.

(xx) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements)(Seventh Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. SEBI/LADNRO/GN/2015-16/025 Gazette of India dated 28th October, 2015.

(xxi) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers)(Fourth Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. SEBI/LADNRO/GN/2015-16/026 Gazette of India dated 22nd December, 2015.

(xxii) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements)(Fourth Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/027 Gazette of India dated 22nd December, 2015.

(xxiii) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements)(Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. SEBI/LADNRO/GN/2016-17/001 Gazette of India dated 25th May, 2016.

(xxiv)The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers)(Second Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. SEBI/LADNRO/GN/2016-17/002 Gazette of India dated 25th May,
2016.

(xxv) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements)(Third Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. SEBI/LADNRO/GN/2016-17/003 Gazette of India dated 25th May, 2016.

(xxvi)The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities)(Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/004 Gazette of India dated 25th May, 2016.

(xxvii) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Redeemable Preference Shares)(Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/005 Gazette of India dated 25th May, 2016.

(xxviii) The Securities and Exchange Board of India (Intermediaries)(Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016- 17/006 Gazette of India dated 25th May, 2016.

(xxix)The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants)(Third Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016- 17/007 Gazette of India dated 27th May, 2016.

(xxx) Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/028 published in Gazette of India dated 6th January, 2016 regarding establishment of Local Office of the Board at Jammu.

(xxxi)The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations)(Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/029 Gazette of India dated 11th January, 2016.

(xxxii) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares)(Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/030 Gazette of India dated 12th January, 2016.

(xxxiii) The SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements)(Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/031 Gazette of India dated 21st January, 2016.

(xxxiv) The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants)(Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/032 Gazette of India dated 21st January, 2016.

(xxxv) Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/033 Gazette of India dated 21st January, 2016 regarding renewal of recognition of MCX-SX Clearing Corporation Limited.

(xxxvi) The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds)(Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. EBI/LAD-NRO/GN/2015-16/034 Gazette of India dated 12th February, 2016.

(xxxvii) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers)(Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. SEBI/LADNRO/GN/2015-16/035 Gazette of India dated 18th February, 2016.

(xxxviii)The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements)(Second Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. SEBI/LADNRO/GN/2015-16/036 Gazette of India dated 18th February, 2016.

(xxxix) The Securities and Exchange Board of India (Regulation)(Stock Exchanges and Clearing Corporations)(Second Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/037 Gazette of India dated 15th March, 2016.

(xl) The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants)(Second Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/038 Gazette of India dated 15th March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 5211/16/16]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act,
2013:-

(i) The Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Amendment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.397(E) in Gazette of India dated 5th April, 2016.

(ii) The Companies (Registration Offices and Fees) Amendment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.493(E) in Gazette of India dated 7th May, 2016.

(iii) The Companies (Authorised to Register) Amendment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.563(E) in Gazette of India dated 31st May, 2016.

(iv) The Companies (Acceptance of Deposits) Amendment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.639(E) in Gazette of India dated 29th June, 2016.

(v) The Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Amendment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.646(E) in Gazette of India dated 30th June, 2016.

(vi) The Companies (cost records and audit) Amendment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.695(E) in Gazette of India dated 14th July, 2016.

(vii) The Companies (Share Capital and Debentures) Third Amendment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.704(E) in Gazette of India dated 19th July, 2016.

(viii) The Companies (Removal of Difficulties) Third Order, 2016 published in Notification No. G.S.R.2264(E) in Gazette of India dated 30th June, 2016.

(4) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item (i) to (ii) of (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 5212/16/16]

(5) A copy of the Limited Liability Partnership (Second Amendment) Rules, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.593(E) in Gazette of India dated 10th June, 2016 under subsection (3) of Section 79 of the Limited Liability Partnership Act, 2008.

[Placed in Library, See No. LT 5213/16/16]

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Securities and Exchange Board of India, Mumbai, for the year 2015-2016 under sub-section (2) of Section 18 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of Securities and Exchange Board of India, Mumbai, for the year 2015-2016.

[Placed in Library, See No. LT 5214/16/16]

(7) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

(i) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 22 of 2016)-Voluntary Compliance Encouragement Scheme, 2013 (Indirect Taxes-Service Tax) Department of Revenue for the year ended March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 5215/16/16]

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil)(No. 23 of 2016)-Performance Audit of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Ministry of Rural Development.

[Placed in Library, See No. LT 5216/16/16]

(iii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil) (No. 24 of 2016)-(Compliance Audit Observations) Union Territories without Legislatures for the year ended March, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 5217/16/16]

(iv) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Commercial) (No. 25 of 2016)-(Compliance Audit) Implementation of PAHAL (DBTL) Scheme (Pratyaksh Hanstantrit Labh Yojana), Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year ended March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 5218/16/16]

(v) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 26 of 2016)-(Compliance Audit) Administrative functioning of Autonomous Bodies under Department of Science and Technology.

[Placed in Library, See No. LT 5219/16/16]

(vi) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil)(No. 27 of 2016)-Compliance of Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, for the year ended March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 5220/16/16]

(8) A copy of Notification No. S.O. 681(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 12th July, 2016, making certain amendments in Notification No. S.O. 38(E) dated 19th January, 2011 under Section 30B of the Chartered Accountants Act, 1949.

[Placed in Library, See No. LT 5221/16/16]

(9) A copy of the Notification No. G.S.R.404(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 6th April, 2016 making certain amendments to Schedule III of the Companies Act, 2013 under sub-section (3) of Section 467 of the Companies Act, 2013.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 5222/16/16]

(11) A copy of the Companies (Removal of Difficulties) Third Order, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.2264(E) in Gazette of India dated 30th June, 2016 under sub-section (2) of Section 470 of the Companies Act, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 5223/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI UPENDRA KUSHWAHA):

On behalf of Dr. Mahendra Nath Pandey, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Atal Bihari Vajpayee-Indian Institute of Information Technology Management, Gwalior, for the year 2014-2015, together with Audit Report thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 5224/16/16]

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the EdCIL (India) Limited, Noida, for the year 2014-2015.

(ii) Annual Report of the EdCIL (India) Limited, Noida, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 5225/16/16]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Project of History of Indian Science, Philosophy and Culture, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Project of History of Indian Science, Philosophy and Culture, New Delhi, for the year 2014-2015.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 5226/16/16]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Raipur, Raipur, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Raipur, Raipur, for the year 2014-2015.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 5227/16/16]

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Tiruchirappalli, Tiruchirappalli, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Tiruchirappalli, Tiruchirappalli, for the year 2014-2015.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 5228/16/16]

(11) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 28 of the University Grants Commission Act, 1956:-

(i) The UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016 published in Notification No. F. No. 1-3/2016(CPPPI/DU) in Gazette of India dated 11th July, 2016.

(ii) The University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D.Degrees) Regulations, 2016 published in Notification No. F. No. 1-2/2009(EC/PS)V(I) Vol.II Preamble in Gazette of India dated 5th July, 2016.

(iii) The University Grants Commission (Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) Regulations, 2015 published in Notification No. F. No. 91-1/2013(TFGS) in Gazette of India dated 2th May, 2016.

(iv) The University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education)(4th Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. F. No. 1-2/2016(PS/Amendment) in Gazette of India dated 11th July, 2016.

(v) The Curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions (Third Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. F. No. 1-15/2009(ARC) in Gazette of India dated 29th June, 2016.

(vi) The University Grants Commission on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher education)(3rd Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. F. No. 1-2/2016(PS/Amendment) in Gazette of India dated 10th May, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 5229/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Brahmaputra Cracker and Polymer Limited and the Ministry of Chemicals and Fertilizers for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 5230/16/16]

(2) A copy of the Notification No. S.O.1594(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 2nd May, 2016, order indicating the supplies of urea to be made by domestic manufacturers of urea to States and Union Territories during Kharif, 2016 under subsection (6) of Section 3 of the Essential Commodity Act, 1955.

[Placed in Library, See No. LT 5231/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding between the Hindustan Aeronautics Limited and the Ministry of Defence for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 5232/16/16]

(ii) Memorandum of Understanding between the Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited and the Ministry of Defence for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 5233/16/16]

(iii) Memorandum of Understanding between the Mazagon Dock Shipbuilders Limited and the Ministry of Defence for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 5234/16/16]

(iv) Memorandum of Understanding between the Mishra Dhatu Nigam Limited and the Ministry of Defence for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 5235/16/16]

(v) Memorandum of Understanding between the Hindustan Shipyard Limited and the Ministry of Defence for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 5236/16/16]

(vi) Memorandum of Understanding between the Goa Shipyard Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 5237/16/16]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 13 of the National Cadet Corps Act, 1948:-

(i) The National Cadet Corps (Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.18 in weekly Gazette of India dated 7th May, 2016.

(ii) The National Cadet Corps (Girls Division) (Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.19 in weekly Gazette of India dated 7th May, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 5238/16/16]

12.05 hours

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
Minutes

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): I beg to lay on the Table the Minustes ((Hindi and English versions) of the Eighteenth to Twenty-fifth sittings of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions held during the Seventh, Eighth and Ninth sessions.

12.05 ½ hours

STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY
Statements

SHRI VIRENDER KASHYAP (SHIMLA): Madam, I beg to lay on the table the following Statements (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Information Technology:-

(1) Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter-I and final replies to the recommendations contained in Chapter-V of the Thirteenth Action Taken Report (16th Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in Fifty-third Report (15th Lok Sabha) on 'Norms for setting up of telecom towers, its harmful effects and setting up of security standards in expansion of telecom facilities' of the Ministry of Communications and Information Technology (Department of Telecommunications).

(2) Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter-I and final replies to the recommendations contained in Chapter-V of the Fifteenth Action Taken Report (16th Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in Third Report (16th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2014-15)' of the Ministry of

Communications and Information Technology (Department of Telecommunications).

(3) Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter-I and final replies to the recommendations contained in Chapter-V of the Fourteenth Action Taken Report (16th Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in First Report (16th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2014-15)' of the Ministry of Communications and Information Technology (Department of Posts).

(4) Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter-I and final replies to the recommendations contained in Chapter-V of the Twentieth Action Taken Report (16th Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in Fifth Report (16th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2015-16)' of the Ministry of Communications and Information Technology (Department of Posts).

(5) Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter-I and final replies to the recommendations contained in Chapter-V of the Twelfth Action Taken Report (16th Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in Forty-seventh Report (15th Lok Sabha) on 'Issues related to Paid News' of the Ministry of Information and Broadcasting.

(6) Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter-I and final replies to the recommendations contained in Chapter-V of the Sixteenth Action Taken Report (16th Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in Fourth Report (16th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2014-15)' of the Ministry of Information and Broadcasting.

(7) Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter-I and final replies to the recommendations contained in Chapter-V of the Nineteenth Action Taken Report (16th Lok Sabha) on the

recommendations of the Committee contained in Eighth Report (16th Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2015-16)' of the Ministry of Information and Broadcasting.

_____

12.06 hours

STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT
12th Report

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी) : अध्यक्ष महोदया, मैं शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित "मुद्रण निदेशालय, भारत सरकार स्टेशनरी आफिस और प्रकाशन विभाग का आधुनिकीकरण" विषय पर शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2015-16) का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.06 ½ hours

STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS
198th Report

SHRI PREM SINGH CHANDUMAJRA (ANANDPUR SAHIB): Madam, I beg to lay on the Table the One Hundred and Ninety-eighth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Home Affairs on Disaster in Chennai Caused by Torrential Rainfall and Consequent Flooding.

12.07 hours

STATEMENTS BY MINISTERS

(i)Status of implementation of the recommendations contained in the 84th and 91st Reports of the Standing Committee on Health and Family Welfare on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Ministry of AYUSH (Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy) *

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Madam, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 84th and 91st Reports of the Standing Committee on Health and Family Welfare on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Ministry of AYUSH (Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy).

_____

12.07 ½ hours

(ii)Status of implementation of the recommendations contained in the 12th and 15th Reports of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers pertaining to the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): Madam, since the Statements are lengthy, I do not want to take the precious time of the House. Hence, I seek your permission to lay the following statements:

(1) Status of implementation of the recommendations contained in the 12th Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on `Functioning of National Institutes of Pharmaceuticals Education and Research', Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 5239/16/16 .

** Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 5240/16/16 and 5241/16/16 respectively.

(2) Status of implementation of the recommendations contained in the 15th Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in the 4th Report of the Committee on `Jan Aushadhi Scheme', pertaining to the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers.

———

(iii)Status of implementation of the recommendations contained in the 6th to 9th Reports of the Standing Committee on Defence pertaining to the Ministry of Defence *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE): Madam, I beg to lay the following statements regarding the:-

(1) Status of implementation of the recommendations contained in the 6th Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants (2015-16) on Civil Expenditure of the Ministry of Defence and Capital Outlay on Defence Services (Demand Nos. 21,22 and 23), pertaining to the Ministry of Defence.

(2) Status of implementation of the recommendations contained in the 7th Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants (2015-16) on Army (Demand No.23), pertaining to the Ministry of Defence.

(3) Status of implementation of the recommendations contained in the 8th Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants (2015-16) on Navy and Air Force (Demand Nos.24 and 25), pertaining to the Ministry of Defence.

(4) Status of implementation of the recommendations contained in the 9th Report of the Standing Committee on Defence on `Ordnance Factories and

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 5242/16/16, 5243/16/16,5244/16/16 and 5245/16/16 respectively.

Defence Research and Development Organisation (Demand Nos. 26 and 27), pertaining to the Ministry of Defence.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, I want to make a small submission.

HON. SPEAKER: What do you want to say? Before Shri Kharge *ji,* you want to speak.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: You assured me that you would allow me.

माननीय अध्यक्ष : क्या हुआ?

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: Hon. Prime Minister is also present here. This entire page….

माननीय अध्यक्ष : बाद में कई सारी बातें होती हैं, सुदीप जी।

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : वह ठीक है। आप बाद में बात कर सकते हैं।

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज सुदीप जी, बैठ जाइए। I am sorry.

… (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : We demand…… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Kharge *ji.*

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Not like this. I am sorry.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम स्पीकर, देश के हित में यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। कश्मीर का मामला...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या हो रहा है? आप आपस में बात मत कीजिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : कश्मीर का मामला दिन प्रति दिन जटिल होता जा रहा है और वहां के हालात भी बिगड़ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं, आपसे अपील करता हूं कि सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव इस सदन में आए, जिससे सारे देश के जनता को भी यह मालूम हो कि पूरा सदन एक है। कश्मीर के विषय में सभी की एक ही राय है और वहां पर शान्ति स्थापित करने के लिए किस-किस ढंग से क्या काम करना चाहिए।

इसके बारे में अगर सरकार इस सदन से सर्वसम्मति से एक रिजोल्यूशन पास कर दे तो यह अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि सरकार इस पर रेस्पौंड करे।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदया, जम्मू-कश्मीर के संबंध में जिस प्रकार के प्रस्ताव की बात हमारे खड़गे जी ने कही है, इसी प्रकार का प्रस्ताव मैंने राज्य सभा में प्रस्तुत किया था और राज्य सभा ने सर्वसम्मति से उसे पारित किया है। वहां पर शान्ति और नॉर्मल्सी को रेस्टोर करने के संबंध में वहां की जनता से अपील की है और जो भी खड़गे जी ने प्रस्ताव रखा है, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Madam Speaker, the Resolution should be moved from the Chair.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, it should be moved from the Chair.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है। मैं रिजोल्यूशन पढ़ती हूं।

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Okay. I will read it.

… (*Interruptions*)

12.11 hours

RESOLUTION BY THE SPEAKER

Restoration of peace and normalcy in Jammu and Kashmir

HON. SPEAKER: Hon. Members, I propose the following resolution:

"That this House

i) expresses its serious concern over the prolonged turbulence, violence and curfew in the Kashmir Valley;

ii) conveys its deep sense of anguish and concern over the loss of lives and critical injuries caused by the deteriorating situation;

iii) is of the firm and considered view that there cannot be any compromise on unity, integrity and national security; it is equally imperative that urgent steps are taken to restore order and peace for the alleviation of the sufferings of the people;

iv) earnestly appeals to all sections of the society in Jammu and Kashmir, to work for the early restoration of normalcy and harmony; and

v) unanimously resolves to restore the confidence among the people in general and youth in particular."

I hope the House agrees.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

The Resolution was adopted.

HON. SPEAKER: So, the Resolution is adopted unanimously. Thank you very much.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Thank you Madam.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, this is the second occasion within a week where the House has agreed unanimously on two subjects, first on the GST Bill and now on this Resolution.

12.13 hours

VALEDICTORY REFERENCE

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सोलहवीं लोक सभा का नौवां सत्र जो 18 जुलाई 2016 को आरंभ हुआ था, आज समाप्त हो रहा है।

इस सत्र के दौरान कुल 20 बैठकें हुईं जो 121 घंटे 23 मिनट चलीं। सभा एक वर्तमान सदस्य और कुछ अन्य पूर्व सदस्यों के निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् 18 जुलाई 2016 को स्थगित हो गई थी।

इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्य का निपटान किया गया। वर्ष 2016-17 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर मतदान और संबंधित विनियोग विधेयक पारित किए जाने से पहले इन पर चर्चा हुई जो 4 घंटे और 53 मिनट तक चली।

वर्तमान सत्र के दौरान 14 सरकारी विधेयक पुर:स्थापित किए गए। कुल मिलाकर 13 विधेयक पारित किए गए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं:- The Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2016, the Dentists (Amendment) Bill, 2016, the Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Bill, 2016, the Benami Transactions (Prohibition) Amendment Bill, 2015, the Enforcement of Security Interest and Recovery of Debt Laws and Miscellaneous Provisions (Amendment) Bill, 2016, the Employees Compensation (Amendment) Bill, 2016, the Taxation Laws (Amendment) Bill, 2016, the Factories (Amendment) Bill, 2016.

सभा में संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 जिसे वस्तु और सेवा कर (जी.एस.टी.), विधेयक भी कहा जाता है, उसमें राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर भी चर्चा हुई। सभा इस विधेयक पर लगभग 6 घंटे चर्चा करने के पश्चात् राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमत हुई।

रेलवे कन्वेंशन कमेटी के प्रथम प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों संबंधी एक सरकारी संकल्प लगभग 4 घंटे की चर्चा के पश्चात् स्वीकृत हुआ।

सत्र के दौरान, 400 तारंकित प्रश्न सूचीबद्ध थे जिनमें से 99 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। इस प्रकार, औसतन, लगभग प्रतिदिन 4.95 प्रश्नों यानी 5 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। शेष तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 4600 अतारंकित प्रश्नों के उत्तरों के साथ सभा पटल पर रखे गए। श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के बारे में उठाई गई आधे घंटे की चर्चा पर भी बहस की गई और संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर दिया।

प्रश्न काल के पश्चात् और शाम को देर तक बैठ कर सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के लगभग 618 मामले उठाए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन भी 367 मामले उठाए। स्थायी समितियों ने 32 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए।

स्थायी समितियों ने 32 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए।

सभा में नियम 193 के अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के विषय, कश्मीर घाटी में हाल में हुई हिंसा, मूल्य वृद्धि, एस.डी.जी., संधारणीय विकास लक्ष्य, जिस पर अभी आंशिक चर्चा हुई और देश में दलितों पर अत्याचार पर, चार अल्पकालिक चर्चाएं भी हुईं। संबंधित मंत्रियों के उत्तर के साथ तीन महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा पूरी हुई।

सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण के जरिए भी दो मामले उठाए गए जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महानदी के ऊपर बैराज परियोजनाओं का निर्माण किए जाने के कारण कथित तौर पर ओडिशा में हीराकुंड बांध में जल-प्रवाह के अत्यधिक बाधित होने और देश में विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन्सेफलाइटिस के फैलने से संबंधित है। ध्यानाकर्षण के उत्तर में, संबंधित मंत्रियों ने वक्तव्य दिए और सदस्यों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों के भी उत्तर दिए।

मंत्रियों द्वारा अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 41 वक्तव्य दिए गए और माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य के संबंध में तीन वक्तव्य दिए गए।

सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों द्वारा 907 पत्र सभा पटल पर रखे गए।

जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का संबंध है, विभिन्न विषयों पर गैर-सरकारी सदस्यों के के 84 विधेयक पुरःस्थापित किए गए हैं। श्री बैजयन्त पांडा द्वारा 26 फरवरी, 2016 को the Rights of Transgender Perssons Bill, 2014 जो कि राज्य सभा द्वारा यथापारित है, इस पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर सभा की सहमति से 5 अगस्त को चर्चा स्थगित कर दी गई। तदनुसार, श्री विन्सेंट पाला द्वारा संविधान की छठी अनुसूची के संशोधन के आश्य वाला विधेयक पेश किया गया। विधेयक पर चर्चा 5 अगस्त, 2016 को अधूरी रह गई।

जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों का संबंध है, कर्मचारी भविष्य निधि पेंशनभोगियों का कल्याण सुनिश्चित करने हेतु उपायों संबंधी संकल्प, जो श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा छठे सत्र के दौरान 11 दिसम्बर, 2015 को पेश किया गया था, उस पर 29 जुलाई, 2016 को चर्चा आरंभ की गई जो अधूरी रही।

सभा ने एक मत से यह प्रस्ताव किया कि कश्मीर के समस्त जनमानस में, विशेषरूप से युवाओं में विश्वास पुनः स्थापित किया जाये। इस सत्र में, जबकि व्यवधानों और बाध्य सदनों के कारण 6 घंटे और 33

मिनट से अधिक का समय नष्ट हुआ। सभा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 18 घंटे और पांच मिनट देर तक बैठी।

भगवंत मान द्वारा सोशल मीडिया पर संसद परिसर के फुटेज को अपलोड करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित की गई है।

मैं सभापति तालिका में शामिल अपने सहयोगियों का सभा के सुचारू संचालन में अपना सहयोग देने के लिए धन्यवाद करती हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं, मुख्य सचेतकों तथा माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के अपने मित्रों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं इस अवसर पर महासचिव और लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके द्वारा सभा को दी गई समर्पित और तत्काल सेवा के लिए धन्यवाद देती हूं। मैं संबद्ध एजेंसियों को, जो सभा की कार्यवाही के संचालन में प्रदान की गई सहायता के लिए भी धन्यवाद देती हूं।

माननीय सदस्यगण, मैं हमारे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और इस बार हमारा 70वां स्वतंत्रता वर्ष शुरू हो जाएगा, इस अवसर पर भी आप सभी को तथा समस्त भारतीयों को देश और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को बधाई देती हूं तथा बधाई के साथ-साथ एक समर्थ, स्वावलंबी एवं सशक्त राष्ट्र बनाने में हम सब सफल हों, यह विश्वास भी व्यक्त करती हूं। माननीय सदस्यगण अब हम कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि 'वन्दे मातरम्' की धुन बजाई जाएगी।

12.22 ½ hours

NATIONAL SONG

National Song Was Played.

HON. SPEAKER: The House stands adjourned sine die.

12.23 hours

The Lok Sabha then adjourned sine die.